187 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर

नई दिल्ली,15 अप्रैल (ए)। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के नेतृत्व वाले छह बैंकों के कंसोर्टियम के साथ 187 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में सीबीआई ने दिल्ली स्थित एक डायमंड ट्रेडिंग कंपनी एसएसके प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है। कंपनी और उसके निदेशकों सुरेंद्र कुमार बंसल और शेफाली बंसल का वांदनी चौक में शोरूम है। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल, 2013 में बैंकों के कंसोर्टियम ने कंपनी को 163 करोड़ रुपए का ऋण दिया था। इसमें पीएनबी का हिस्सा 55 करोड़ रुपए का था। 30 जून, 2014 को यह ऋण गैर निष्पादक संपत्तियों (एनपीए) में तब्दील हो गया। ब्याज की अदायगी नहीं होने की वजह से ऋण की कुल राशि बढ़ गई थी। एफआईआर के मुताबिक, ऋण के लिए गिरवी रखी गई संपत्तियों की कीमत काफी बढ़ा-चढ़ाकर प्रदर्शित की गई थी और आरोपितों ने उन्हें बेच भी दिया। बता दें कि बैंकों के इस कंसोर्टियम में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आंध्र बैंक, सिंडीकेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स भी शामिल हैं।

आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर बिना ड्राइवर के दौड़ा इंजन, तीन पहिये बेपटरी; चालक निलंबित

नई दिल्ली,15 अप्रैल (ए)। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर शनिवार दोपहर बिना ड्राइवर के इंजन चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद इंजन पटरी से उतर गया। गनीमत रही कि इससे कोई हादसा नहीं हुआ। मामले में लापरवाही बरतने पर चालक को निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार आनंद विहार स्टेशन के यार्ड में लाइन नंबर 5ए पर डीजल इंजन खड़ा था। अचानक दिन में दोपहर 2:33 बजे इंजन चल पड़ा। करीब 40 मीटर चलने के बाद इंजन के तीन पहिये रेल लाइन से नीचे आ गए। हालांकि, इससे रेल यातायात बाधित नहीं हुआ। मामले में रेलवे अधिकारी कुछ भी आधिकारिक रूप से बोलने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि यार्ड में इंजन को खड़ा करते समय हैंड ब्रेक लगाया जाता है। चालक की लापरवाही की वजह से यह घटना हुई है। जिम्मेदार चालक को निलंबित कर दिया गया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यार्ड में इंजन बंद करने के बाद पार्क किए जाते हैं। पार्क करते समय हैंड ब्रेक भी लगाया जाता है। कभी भी इस तरह की घटना नहीं होती है। अगर हैंड ब्रेक सही तरीके से लगाए गए होते तो इंजन स्वत- आगे नहीं बढ़ता।

नीतीश कुमार का ऐलान, अब एससी/एसटी श्रेणी को भी मिलेगा महादलित श्रेणी का फायदा

पटना,15 अप्रैल (ए)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि राज्य में 'महादलितों' के लिए बनी सभी योजनाओं का लाभ अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को भी मिलेगा। नीतीश ने कहा, हमने फैसला किया है कि राज्य में महादलितों के विकास के लिए महादलित विकास मिशन द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ अजा और अजजा वर्ग के लोगों को भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि सभी योजनाएं चाहे वह घर बनाने के लिए जमीन देना हो या दशरथ मांझी कौशल विकास योजना हो - सभी का लाभ अजा और अजजा श्रेणी के तहत आने वाले लोगों को भी दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि एक ' चौकीदार ' के आश्रित को वही नौकरी मिल सकती है अगर वह उसकी सेवानिवृत्ति से पहले आवेदन करे तो। नीतीश ने चौकीदारों के मानदेय को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये सालाना करने की भी घोषणा की। आज की इस घोषणा के साथ ही पासवान (दुधाव समुदाय) जिन्हें महादलित श्रेणी से अलग किया गया था वह अब फिर से इस श्रेणी में शामिल हो गए। नीतीश ने यह घोषणा बी आर आंबेडकर की जयंती के मौके पर आयोजित दलित सेना के राष्ट्रीय सम्मेलन में की।

रेप मामले में महिला थाना प्रभारी की भूमिका संदिग्ध, लाइनहाजिर

सिरसा,15 अप्रैल (ए)। गांव आनंदगढ़ में विवाहिता से सुहागरात के दिन दुष्कर्म मामले में तत्कालीन महिला थाना प्रभारी सुशीला बाला की भूमिका संदिग्ध होने के चलते उसे शुक्रवार रात्रि लाइनहाजिर कर दिया। उल्लेखनीय है कि महिला थाने ने गांव आनंदगढ़ निवासी एक विवाहिता की शिकायत पर उसके चाचा ससुर व ननदोई के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था। महिला ने बताया था कि सुहागरात को उसका चाचा ससुर और ननदोई उसके पति को लेकर कक्ष में आए। पति नशे में चूर था और चाचा ससुर ने उसके साथ दुष्कर्म किया जबकि ननदोई ने उसका मुंह बंद रखा। मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से मामले को झूठा बताया गया। आनंदगढ़ की पंचायत और ग्रामीणों ने दुष्कर्म के आरोपों को खारिज किया और इसे झूठा बताया। जांच ए.एस.पी. नरेंद्र बिजरानियां को सौंपी गई। बताया जाता है कि मामले में ए.एस.पी. ने दोनों पक्षों की पंचायत बुलाई और महिला थाना प्रभारी की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर उसे लाइनहाजिर करने का निर्णय लिया। अपने चाचा ससुर और ननदोई पर दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाने वाली विवाहिता ने शादी के पहले ही दिन महिला थाना में मायका पक्ष पर उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करवाने का आरोप लगाया था।

यूपी बोर्ड परीक्षा छोड़ने वालों में दुबई, सऊदी अरब, दोहा निवासियों की बड़ी तादाद

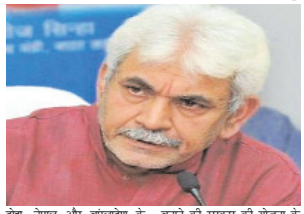

लखनऊ,15 अप्रैल (ए)। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की परीक्षा में अप्रत्याशित संख्या में विदेशी छात्रों की क्या दिलचस्पी हो सकती है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने इसका चौंकाने वाला खुलासा करते हुए आज बताया कि इस साल सख्ती के कारण इम्तेहान छोड़ने वाले 11 लाख छात्र-छात्राओं में दुबई, दोहा, कतर और नेपाल के 'परीक्षार्थी' भी शामिल हैं, जिससे संकेत मिलता है कि प्रदेश में नकल का कारोबार कहां तक फैला था। शर्मा ने बताया कि इस साल बोर्ड परीक्षाओं के दौरान सरकार की जबर्दस्त सख्ती के कारण लाखों छात्र-छात्राओं का परीक्षा छोड़ना खासा सुर्खियों में रहा। परीक्षा छोड़ने वालों के बारे में जानकारी का बारीकी से विश्लेषण करने पर चौंकाने वाले तथ्य सामने आये हैं। उन्होंने हैरान करने वाला खुलासा करते हुए बताया कि इस साल यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडियट की परीक्षाओं में सख्ती के कारण इम्तेहान छोड़ने वाले 11 लाख छात्र-छात्राओं में 75 प्रतिशत तादाद दूसरे राज्यों और देशों के निवासियों की है। परीक्षा छोड़ने वालों में सऊदी अरब, दुबई, कतर, दोहा, नेपाल और बांग्लादेश के नागरिक भी शामिल हैं। इससे जाहिर होता है कि यूपी बोर्ड में नकल माफिया के तार कहां-कहां तक फैले हैं। सरकार इस नेटवर्क को छिन्न-भिन्न करेगी। राज्य के माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग का जिम्मा भी सम्भाल रहे शर्मा ने बताया कि सरकार ने ठेका लेकर नकल के जरिये परीक्षा पास कराने वाले माफिया का खेल खत्म करने के लिये राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स और स्थानीय अभिसूचना तंत्र का प्रभावी इस्तेमाल किया। भविष्य में भी परीक्षाओं को पूरी तरह नकलविहीन बनाने की सरकार की योजना के बारे में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सभी परीक्षा केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया है। इससे नकल पर रोक लगाने में बहुत मदद मिली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 10 हजार से ज्यादा विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने पर 400 करोड़ रुपये से ज्यादा की धनराशि की जरूरत होगी। सरकार के पास इतना बजट नहीं है। ऐसे में यह तय किया गया कि जिन स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और जिनकी चहारदीवारी दुरुस्त होने के साथ-साथ अन्य जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं, केवल उन्हीं को परीक्षा केन्द्र बनाया जाएगा।

शर्मा ने आगामी परीक्षाओं के बारे में पूछे जाने पर कहा कि अगले साल बोर्ड परीक्षा के फार्म भरने वाले कक्षा नौ और कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिये आधार कार्ड संलग्न करना अनिवार्य बना दिया गया है। इससे उनकी पहचान करने और भविष्य में नकल रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने परीक्षाओं में नकल रोकने के लिये सभी मुमकिन रास्तों का अध्ययन किया है। अब दूसरे के नाम पर परीक्षा देने वाले या उत्तर पुस्तिकाएं बदलने वाले तत्व अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकेंगे। मालूम हो कि इस साल छह फरवरी से 12 मार्च तक हुई यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिये कुल 66 लाख 37 हजार 18 छात्र-छात्राओं ने फार्म भरा था। इन परीक्षाओं के परिणाम इस महीने के अंत में घोषित होंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार बोर्ड परीक्षाओं के टॉप विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी, ताकि छात्र-छात्राएं उन्हें देखकर प्रेरणा लें और तैयारी करें।

एक महीने में यूको बैंक का दूसरा घोटाला आया सामने, पूर्व सीएमडी पर केस दर्ज

नई दिल्ली,15 अप्रैल (ए)। सीबीआई ने यूको बैंक में 621 करोड़ के घोटाले में बैंक के पूर्व सीएमडी अरुण कौल और कई अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जांच एजेंसी ने शनिवार को इसी सिलसिले में 10 जगहों पर छापेमारी भी की। इनमें से अधिकतर ठिकाने मुंबई और दिल्ली में हैं। माना जा रहा है कि आरोपियों ने आपराधिक साजिश के तहत बैंक के लोन में हेराफेरी कर यूको बैंक से लगभग 621 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है। बता दें कि अरुण कौल 2010 से 2015 के बीच यूको बैंक के सीएमडी थे। इसके बाद सरकार ने उनके कार्यकाल को बढ़ाने से इंकार कर दिया। जांच एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि कौल के अलावा एरा इंजीनियरिंग इंफ्रा इंडिया लिमिटेड के सीएमडी हेम सिंह भराना, दो चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज जैन और वंदना शारदा, मेसर्स अलंटियस फिन्सर्व प्राइवेट लिमिटेड के पवन बंसल और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि एक महीने के अंदर यूको बैंक का यह दूसरा घोटाला है। इससे पहले सीबीआई ने महीने की शुरुआत में कर्नाटक में यूको बैंक में 19.03 करोड़ के घोटाले का मामला दर्ज किया था। जिसमें 18 लोगों ने गलत नामों से विभिन्न योजनाओं में हीरा और प्रॉपर्टी लोन लिया था। बैंक ने 27 मार्च को मामले की जांच के लिए सीबीआई से अपील की थी।

पंजाब में दो समुदायों में टकराव, हिंसा के बाद भारी पुलिस बल तैनात

कपूरथला/चंडीगढ़,15 अप्रैल (ए)। कपूरथला के फगवाड़ा में दो समुदायों में हुए टकराव के बाद माहौल और तनावपूर्ण हो गया। शनिवार सुबह शिवसेना पंजाब के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश पलटा पर कुछ युवकों ने सुभाष नगर चौक के पास हमला कर दिया। इसके बाद उन्हें निर्वस्त्र कर पीटा गया। इसका वीडियो वायरल होने के बाद तनाव बढ़ता देख शहर में अर्ध सैनिक बलों की नौ कंपनियां व पुलिस के तीन हजार जवान तैनात कर दिए गए हैं। इनमें आठ कंपनियां बीएसफ व एक कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स की है। पुलिस ने दोनों समुदायों के 450 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। गौरतलब है कि फगवाड़ा के बस स्टैंड के पास स्थित गोल चौक पर शुक्रवार को एक समुदाय ने डॉ. भीम राव आंबेडकर की तस्वीर व संविधान चौक नाम का बोर्ड लगा दिया था। इसके बाद दो समुदायों में रात को टकराव हो गया। सुबह चक्क हकीम स्थित श्री गुरु रविदास मंदिर व हनुमानगढ़ी मंदिर में दोनों समुदायों की बैठकें होती रहीं। डीसी मोहम्मद तय्यब व एसएसपी संदीप शर्मा ने दोनों पक्षों के साथ बैठक कर शांति बनाए रखने की अपील की। उधर, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चार जिलों जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर व एसबीएस नगर (नवांशहर) में 24 घंटे तक मोबाइल व इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश जारी कर घटना की जांच के आदेश दिए हैं।

चीन के आर्थिक विकास को मिलने वाला गैर बाजारी निर्देश बढ़ा रहा जोखिम : अमेरिका

वॉशिंगटन,15 अप्रैल (ए)। अमेरिका ने चेताया है कि चीन के आर्थिक विकास को मिलने वाला गैर बाजारी निर्देश उसके प्रमुख व्यापारिक भागीदारों और दीर्घकालिक वैश्विक वृद्धि परिदृश्य के लिए जोखिम को बढ़ाता है।

अमेरिका के वित्त विभाग ने संसद में एक रिपोर्ट में कहा कि चीन के आर्थिक विकास को मिलने वाला गैर बाजार निर्देश उसके प्रमुख व्यापारिक भागीदारों और दीर्घकालिक वैश्विक वृद्धि परिदृश्य के लिए जोखिम बढ़ा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन को वृहद आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाना चाहिए ,जो कि घरेलू खपत में वृद्धि का समर्थन करते है और अर्थव्यवस्था को संतुलित करने में मदद करते हैं।

चीन का अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष बहुत अधिक है, जो कि अमेरिका के अब तक के किसी भी प्रमुख व्यापारिक भागीदारों में से सबसे अधिक है। दिसंबर 2017 में व्यापार अधिशेष 375 अरब डॉलर पर था , यह 2016 से 28 अरब डॉलर अधिक है। ट्रंप प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वह वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण व्यापार असंतुलन से चिंतित है और निष्पक्ष तथा एक - दूसरे के लिए परस्पर बराबर अवसर प्रदान करने वाले व्यापार सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है।

स्वच्छता में भी एम्स नंबर एक, सरकार देगी ढाई करोड़ का इनाम

नई दिल्ली,15 अप्रैल (ए)। देश का सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान एम्स (ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस) स्वच्छता में भी नंबर एक है। अस्पतालों में सफाई को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे कायाकल्प अभियान के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के 11 अस्पतालों को बेहतर सफाई के लिए 10 करोड़ रुपए इनाम के रूप में देने का फैसला किया है।

इसके तहत एम्स का वर्ष 2017-18 के सबसे स्वच्छ सरकारी अस्पताल के रूप में चयन किया गया है। इसके लिए एम्स को ढाई करोड़ रुपए इनाम के रूप में मिलेंगे। वहीं, सफदरजंग अस्पताल को भी सफाई में सुधार के लिए 50 लाख रुपए इनाम के रूप में देने का फैसला किया गया है। इन दिनों केंद्र सरकार के अस्पतालों में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सफाई अभियान चल रहा है, जो रविवार को समाप्त हो जाएगा। बताया जा रहा है कि 19 अप्रैल को मंत्रालय द्वारा इनाम की औपचारिक घोषणा की जाएगी। मंत्रालय ने चिकित्सा संस्थानों के अनुसार अस्पतालों को दो श्रेणियों (ए व बी) में बांट कर इनाम देने का फैसला किया है। ए श्रेणी के अस्पतालों में एम्स को सफाई के मामले में पहले नंबर पर रखा गया है, जबकि पीजीआई चंडीगढ़ को दूसरा स्थान मिला है। इस अस्पताल को डेढ़ करोड़ रुपए की इनामी राशि मिलेगी।

वहीं, पुडुचेरी स्थित जिपमेर को सफाई के मामले में तीसरा व दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल को चौथा स्थान मिला है। इन दोनों अस्पतालों को 50-50 लाख रुपए मिलेंगे। सफदरजंग अस्पताल को पहली बार बेहतर सफाई के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। हालांकि, एम्स व सफदरजंग अस्पताल की सफाई में बहुत अंतर है। खासतौर पर शौचालयों की सफाई को लेकर सफदरजंग अस्पताल पर सवाल उठते रहे हैं।

अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राजेंद्र शर्मा ने कहा कि शौचालयों में सफाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। अस्पताल में हर हाल में बेहतर साफ सफाई सुनिश्चित की जाएगी। दिल्ली के राष्ट्रीय टीबी व श्वास रोग संस्थान को भी मिलेंगे 50 लाख रुपए बी श्रेणी के अस्पतालों में शिलांग स्थित नार्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस को डेढ़ करोड़ व धुवनेश्वर एम्स को एक करोड़ रुपए पुरस्कार के रूप में देने का फैसला किया गया है।

सामाजिक न्याय के लिए अंबेडकर के अथक प्रयासों ने उन्हें महान बनाया : संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र, 15 अप्रैल (ए)। संयुक्त राष्ट्र के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि वंचित व पिछड़े वर्ग को राजनीतिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में भीमराव आंबेडकर द्वारा किये गये ''अथक प्रयासों'' ने दुनिया में उन्हें एक महान ''प्रवर्तक'' बनाया और समानता और सामाजिक न्याय की उनकी दृष्टि की छाप संयुक्त राष्ट्र के 2030 विकास एजेंडे में झलकती है। आंबेडकर के 127 वें जयंती के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन द्वारा संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में अपने संबोधन में डेवलपमेंट प्रोग्राम ऐडमिनिस्ट्रेटर अकीम स्टेनर ने कहा कि सतत विकास अंबेडकर की ''समतावादी दृष्टि'' का मूल मर्म थी।

उन्होंने कहा, ''आंबेडकर समझते थे कि समाज में बढ़ती असमानताएं राष्ट्र और लोगों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए बुनियादी चुनौतियां पैदा करती है।'' स्टेनर ने कहा, ''वंचित व दलित समुदायों को राजनीतिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाने, ताकि श्रमिकों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार हो और समाज के हरेक व्यक्ति को शिक्षा मिले, इस दिशा में उनके द्वारा किये गये अथक प्रयासों ने उन्हें भारत और अन्य देशों में एक प्रवर्तक के रूप में पहचान दी।

उन्होंने कहा, ''समान अवसर और उस तक पहुंच सुनिश्चित कर सभी के लिए विकास करने की डॉ. आंबेडकर की दृष्टि का सार सतत विकास के लिए 2030 एजेंडे में भी निहित है।'' स्टेनर ने कहा कि भारत सरकार ने अपने विकास एजेंडे के केंद्र में 'सबका साथ सबका विकास' के विचार को रखकर भारतीय संविधान के निर्माता के आदर्शों को कायम रखने की अपनी गहरी प्रतिबद्धता को प्रस्तुत किया है।

सुरक्षा परिषद में रूसी प्रस्ताव गिरा, अमेरिका फिर करेगा कार्रवाई

संयुक्त राष्ट्र,15 अप्रैल (ए)। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीरिया पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के हमले की निंदा का रूसी प्रस्ताव विचार के लिए स्वीकार किए जाने की प्रक्रिया भी पूरी नहीं कर सका। रूसी प्रस्ताव को समर्थन के लिए आवश्यक नौ सदस्य नहीं मिले, इसके परिणामस्वरूप वह प्रक्रिया के शुरुआती चरण में ही गिर गया।

प्रस्ताव को रूस के अतिरिक्त सिर्फ चीन और बोलीविया का ही समर्थन मिल सका। आठ देशों ने प्रस्ताव पर विरोध जताया, जबकि चार सदस्य अनुपस्थित रहे। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में किसी भी प्रस्ताव के पारित होने के लिए उसे नौ सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। साथ ही वीटो अधिकार वाले स्थायी सदस्यों- अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन का भी विरोध नहीं होना चाहिए। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत निक्की हेली ने साफ किया कि सीरिया में अगर दोबारा रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो अमेरिका और मित्र देश फिर से उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। सीरिया को एस-300 मिसाइल सिस्टम दे सकता है रूस रूस, सीरिया के समर्थन में उतर आया है। रूसी कर्नल-जनरल सर्गेई रुडस्कोई ने शनिवार को बताया कि रूस सीरिया और अन्य देशों को एस-300 मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति करा सकता है। रुडस्कोई ने साथ ही कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगियों ने सीरिया पर जो मिसाइल दागी हैं, उनसे वहां की स्थिति और खराब हो जाएगी। उन्होंने बताया कि सीरिया के ज्यादातर शहरों में अब स्थिति शांत है।

मध्य अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर, तीन की मौत
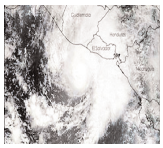
मिनियापोलिस,15 अप्रैल (ए)। मध्य अमेरिका में गल्फ कोस्ट से लेकर ग्रेट लेक्स तक बने तूफान के एक तंत्र ने भारी तबाही मचाई है। तूफान की वजह से भारी बर्फबारी , तेज हवाएं और गरज - चमक के साथ बारिश के चलते उड़ानों को रद्द करना पड़ा , सड़कें खराब हो गई और दो साल की एक बच्ची समेत तीन लोगों को जान गंवानी पड़ी। अपर मिडवेस्ट में तूफान की वजह से भारी बर्फ पड़ी है । यह इलाका सूरज की रोशनी और गर्माहट के लिये परेशान है। मिनियापोलिस के सेंट पॉल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब 400 उड़ानों को रद्द किया गया है वहीं बर्फानी तूफान की वजह से साउथ डकोटा के सबसे बड़े शहर सियोक्स फाल्स लगातार दूसरे दिन भी बंद रहा। अधिकारियों ने दक्षिण पश्चिम मिनिसोटा में कई राजमार्गों को भी बंद कर दिया है और राज्य के दक्षिणी हिस्से में आवागमन के लिये स्थितियां बेहद प्रतिकूल हैं और इन मार्गों पर गाड़ी चलाना काफी मुश्किल है। नेशनल वेदर सर्विस ने पूर्वानुमान व्यक्त किया था कि मिनियापोलिस और सेंट पॉल समेत दक्षिणी मिनिसोटा के एक बड़े हिस्से में रविवार तक 20 इंच (51 सेंटीमीटर) तक बर्फ गिरेगी। उत्तरी विस्कॉंसिन में शनिवार को 18 इंच तक बर्फबारी हुई जबकि रविवार को यहां 14 इंच तक बर्फबारी होने का अनुमान है। साउथ डकोटा में भी कई हिस्सों में भारी बर्फबारी ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है।